

with the Doordarshan during the last one year;

(b) what are the details of the programmes in which these groups participated;

(c) the remuneration paid to each group; and

(d) what are the criteria laid down for associating such groups with Doordarshan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

कच्छ को लाभान्वित करने वाला दूरदर्शन केन्द्र

1956. श्री बीजा ईशदिवेग ऐयुबवेग :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के कच्छ क्षेत्र को किस टी० वी० केन्द्र से लाभान्वित किया जा रहा है ; यह केन्द्र वहाँ से कितनी दूरी पर है ;

(ख) क्या कच्छ से पाकिस्तान का अंतर काफी कम होने की वजह से अन्य देशों द्वारा टेलीविजन पर सांस्कृतिक आक्रमण के खतरे से सरकार अवगत है ; और

(ग) क्या इस परिस्थिति को देखते हुए, निवारक उपाय के रूप में कच्छ को स्वतंत्र दूरदर्शन केन्द्र से संबद्ध करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जब राजकोट और द्वारका में उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन

ट्रांसमिटर पूरी शक्ति पर चालू हो जाएंगे तब उनसे गुजरात के कच्छ क्षेत्र के भागों में सेवा उपलब्ध होने का उम्माद है । राजकोट और द्वारका के ट्रांसमिटर्स से कच्छ क्षेत्र क्रमशः लगभग 105 किलोमीटर और 70 किलोमीटर दूर है ।

(ख) और (ग) जा हाँ । देश में दूरदर्शन सेवा का विस्तार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है कच्छ सहित समावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था करने के काम को उच्च प्राथमिकता दी जा रहा है और इसे भावा योजनाओं में हाथ में लिया जाएगा ।

Uniform Civil Code

1957. SHRI NARENDRA SINGH: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the second National Conference on Women's Studies held in Trivandrum in April, 1964 has demanded to the Central Government for the establishment of a uniform civil code with a view to ensuring equal rights for women and men in all aspects of personal and public life; and

(b) if so, what decision has been taken by Government on this demand?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGANNATH KAUSHAL): (a) Yes, Sir.

(b) Enactment of a Uniform Civil Code will require changes in the personal laws of the minority communities. Policy of the Government has been that no change would be effected in the personal laws of the minority communities whether through the enactment of a Uniform Civil Code or

through the enactment of a law applicable to a particular community unless the initiative therefor comes from the community itself.

Wrong translation on Inland Letter Card

1958. SHRI K. MOHANAN:
SHRI NIRMAL CHATTER-
JEE:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether attention of the Government has been drawn to the wrong translation in English on the inland letter from Hindi as it is printed—"Untouchability is a crime against God and man" instead of "Humanity"; and

(b) if so, what is the reaction of Government thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI VIJAY N. PATIL): (a) Yes, Sir.

(b) The English version of the slogan was taken from Vol. 70 of the "Collected Works of Mahatma Gandhi" (page 184).

Effect of MRTP Amendment Act on Industrial unit

1959. SHRI NARENDRA SINGH:
SHRIMATI MAIMOONA
SULTAN:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Government's attention has been drawn to the statement of the President of the Associated Chambers of Commerce and Industry as reported in the Financial Express of May 4, 1984 to the effect that the recent amendment to the Monopolies and Restrictive Trade - Practices Act, would only be promoting the growth of sickness and

obsolescence of industrial units in the country; and

(b) whether Government have examined the statement and what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGANNATH KAUSHAL): (a) and (b) Yes, Sir. Government's attention has been drawn to the statement of the President of the Associated Chambers of Commerce and Industry, as reported in the Financial Express of May 24, 1984 in regard to the effect of the recent amendment to the MRTP Act on industrial units but the Government does not agree with the views expressed therein.

बिधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग

1960. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
क्या बिधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में नियमानुसार प्रतिवर्ष हिन्दी सलाहकार समिति को चार बैठकें न बुलाए जाने के क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित कौनसे कार्य-क्रम को क्रियान्वित न किए जाने के कारण क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राजभाषा कार्यान्वयन समिति पर है और स्वयं इस समिति के सदस्य भी समिति की बैठकों में भाग नहीं लेते क्योंकि वे हिन्दी के काम को उचित महत्व नहीं देते और यही मुख्य कारण है कि इस मंत्रालय में हिन्दी से संबंधित कोई काम नहीं हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ